

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं0 1607  
15 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

सामान्य पूल रिहायशी आवास

+1607. श्री एस. रामलिंगमः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में सरकारी कर्मचारियों की सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) कॉलोनियों का पुनर्विकास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार परियोजना-वार ऐसी कितनी जीपीआरए परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं;

(घ) परियोजना-वार ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ.) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): जी हां। नौरोजी नगर, सरोजिनी नगर और नेताजी नगर में जीपीआरए कॉलोनियों का पुनर्विकास एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है और श्रीनिवासपुरी, कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर और मोहम्मदपुर में जीपीआरए कॉलोनियों का पुनर्विकास सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है।

(ग): आज की स्थिति के अनुसार, मोहम्मदपुर और त्यागराज नगर में जीपीआरए परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(घ): प्रक्रियाधीन जीपीआरए परियोजनाएं और उनके पूरा होने की संभावित तारीख निम्नानुसार है:

क्र. सं०.	जीपीआरए परियोजनाएं	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
1.	नौरोजी नगर	30.06.2023
2.	नेताजी नगर	30.06.2025
3.	सरोजिनी नगर	31.12.2025
4.	कस्तूरबा नगर	31.03.2025
5.	श्रीनिवासपुरी	31.03.2025

(ड.): जीपीआरए कॉलोनियों का पुनर्विकास स्व-स्थायी वित्तपोषण मॉडल पर अर्थात् "वित्तपोषण के वैकल्पिक मोड" के माध्यम से भारत सरकार से किसी भी बजटीय सहायता के बिना किया जा रहा है।

-----